सौर पम्प से होगी खेतों की सिंचाई, बिहार सरकार

अररिया। अब किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा बिहार सरकार ने किसानों के इस समस्या का हल खोज लिया है। अब किसानों को भाड़े पर पंपसेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी7 अब खुद ही किसान अपने खेतों में सौर उर्जा चलित पंप लगाकर अपने खेत की सिंचाई कर सकता है7 राज्य सरकार ने पूरे बिहार में बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना की शुरूआत की है। राज्य के कुछ प्रखंडों में इस योजना के तहत काम शुरू कर दिया है। जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के पलासी व जोकीहाट प्रखंड का चयन किया गया है। प्रथम चरण में दोनों प्रखंड से 112 किसानों को इसका लाभ उठाएंगे। बिहार सरकार के उर्जा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दो माडल का पंप अधिसूचित किया जाएगा। मैनुअल ट्रैक वाला माडल का अर्थ है कि सौर पैनल को उपभोगकर्ता द्वारा स्वयं सूर्य की स्थिति के हिसाब से सूर्याभिमुख करना होगा। वहीं दूसरा माडल आटो ट्रैक वाला है। जिसमें सौर पैनल अपने आप सूर्य की स्थिति में सूर्याभिमुख हो जाता है। मैनुअलट्रैक माडल सौर पंप की कुल कीमत 2,93,540 रुपया है। इसमें किसान को 12 हजार रुपया मेनटेनेंस खर्च मिलाकर कुल 40154 रुपया राशि देनी होगी शेष राशि 2,53,386 रु. राज्य सरकार द्वारा देय होगी। वहीं आटो ट्रैक माडल की कुल कीमत 3,31400 रु. है जिसमें से किसान को 47,900 रुपया देना होगा तथा शेष 2,83,500 रु. राज्य सरकार भुगतान करेगी। उर्जा सचिव संदीप पौंड्रीक ने डीएम को जल्द योजना चालू कराने को कहा है। डीएम के आदेशानुसार इच्छुक किसान अपना आवेदन 15 जुलाई तक डीएम कार्यालय में जमा कर सकते है।

हिमाचल में आई बाढ़ से सेब की फसल हुई आहत

शिमला। किन्नौरी सेब तो सभी को पसंद होते है। हिमाचल पर आई प्राकृतिक आपदा ने सेब की फसल को भारी नुकसान पहुचाया है7 हिमाचल में होनेवाली किन्नौरी सेब की फसल लगभग सितम्बर खत्म होने तक बाजारों में आ जाती है। लेकिन मौसम की नाराजगी से अक्टूबर से दिसंबर में बाजार में आनेवाले किन्नौरी सेब दिखना मुश्किल हो जायेंगे7 आजादपुर मंडी में शिमला मर्चेंट असोसिएशन के प्रेजिडेंट और सेब कारोबारी दीपक धवन ने कहा कि इस साल किन्नौरी सेब की सप्लाई 60 फीसदी तक कम रहेगी7 हिमाचल में आई बाढ़ से किन्नौर और उसके आसपास के जिलों में सेब की फसल की भयंकर तबाह हुई है। हिमाचल सरकार के बागबानी विभाग का अनुमान है कि किन्नौर में सेब की करीब 70 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है। हिमाचल सरकार के अनुमान के मुताबिक सेब के फसलों की बर्बादी से राज्य को करीब 1500 करोड़ का नुकसान होगा।

आजादपुर मंडी में कारोबारी ने बताया कि इस साल किन्नौरी सेब खाने के लिए लोग तरस जायेंगें7 करीब 10,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर किन्नौर और लाहौल स्फीति के सेब भारत ही नहीं दुनिया में मशहूर हैं। इसकी फसल सितंबर के आखिरी पखवाड़े से बाजार में आने लगती है। इस साल फसल भी अच्छी आई थी7 पैदावार तकरीबन 25 लाख टन होने का अनुमान था। जिसमें से करीबन 40 फीसदी फसल सीधे आजादपुर मंडी पहुंचती है, जहा से अन्य जगहों पर पहुचाई जाती है7 लेकिन

प्राकृतिक आपदा से अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। चेयरमैन राजिंदर कुमार ने बताया कि अब तक हिमाचल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक फसल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा। यह तय है कि इस सीजन में वहां से आधी फसल नहीं आएगी, लेकिन ट्रेडर ने ईरान और कई दूसरे देशों से सेब निर्यात करने का निर्णय लिया है7 जिसकी वजह से इस साल सेब खाना महंगा पड सकता है7

किसान अधिकार पत्र दिलाएगा किसानों को अधिकार

गुड़गांव। किसानों के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में किसान अधिकार पत्र जारी कर दिया है7 भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि अब किसान सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे बल्कि अपना अधिकार मांगेंगे।

किसान अधिकार पत्र पर 16 अगस्त से 5 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। जिसमें किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सभी 28 राज्यों में राजभवन की तरफ कूच करेंगे। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसान मोर्चा ने किसान अधिकार पत्र को जारी कर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि से संबंधित अध्याय की नींव रख दी है। सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार आने पर भाजपा इस अधिकार पत्र को लागू करवाने का काम करेगी।धनखड़ ने बताया कि इस अधिकार पत्र में किसानों को लाभकारी मूल्य का अधिकार, खरीद एवं बोनस का अधिकार, जोखिम में सुरक्षा का अधिकार, सस्ती पूंजी उपलब्धता का अधिकार, किसान मित्रवत आर्थिक संस्थाओं व बैंकिंग का अधिकार, अधिकतम

देनदारी की सीमा का अधिकार, सब्सिडी का अधिकार, भूमिका मालिकाना अधिकार, हर खेत को सिंचन का अधिकार, बीज अधिकार, उर्वरक व कीट, खरपतवारनाशक की उपलब्धता व मलकियत का अधिकार, सिंचन के लिए बिजली की उपलब्धता का अधिकार, कृषि उपकरणों की मिल्कियत का अधिकार, किसानों के लिए बुढ़ापा पेंशन का अधिकार और दुर्घटना एवं बीमारी में इलाज का अधिकार दिलाने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी एवं सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, हरियाणा भाजपा के प्रभारी जगदीश मुखी, किसान मोर्चा के महामंत्री राजेश ठाकरान, जिला उपाध्यक्ष बिजेंद्र डागर, उपाध्यक्ष कर्मचंद यादव, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग बख्शी, पूर्व वाइस चांसलर एवं मोर्चा के नेता लोकेश शेखावत आदि नेता मौजूद थे7

मक्का की नई किस्म

गुजरात आनंद यलो हायब्रिड मेज-1 विकसितअहमदाबाद। वैज्ञानिकों ने मक्का की नई हाईब्रिड किस्म विकसित की है। इसकी खासियत दोगुने से ज्यादा पैदावार देने की इसकी क्षमता है। गुजरात के आनंद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस किस्म के मक्का की खेती राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में हो सकती है। गुजरात आनंद यलो हाइब्रिड मैज-1 (जीएवाई एचएम) नामक इस बीज को प्रदेश के बारिश सिंचित उत्तर व मध्य क्षेत्र में खरीफ सीजन में रोपी जा सकती है। इसके बारे में एएयू के अनुसार निदेशक के.बी. कठेरिया ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र के लिए यह बेहतर विकल्प है। इसे अगले वर्ष तक किसानों को खेती करने के लिये उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह बीज हरियाणा के हिस्सार द्वारा विकसित बीज एचक्यूपीएम से अधिक उत्पादन देता है। हिसार द्वारा विकसित बीज से एक हेक्टेयर क्षेत्र में 1439 किलो तक उत्पादन करने की क्षमता है जबकि जीएवाईएचएम 4000 किलो तक उत्पादन दे सकता है। उन्होंने बताया कि इस बीज को स्टेट रिसर्च कांउसिल से मान्यता मिल चुकी है। यह बीज जीएम द्वितीय से भी 24 फीसदी अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इसकी फसल 80-85 दिनों में तैयार हो जाती है जबकि अन्य किस्मों को तैयार होने में 100 से 120 दिन तक लग जाते हैं। अनुसंधान निदेशक ने बताया कि अन्य मक्का किस्मों की तुलना में इसमें 2.85 फीसदी अधिक प्रोटीन है, जो आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिये बेहतर है। ज्ञातव्य है कि साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, दाहोद सहित गुजरात के अन्य क्षेत्र में भारी मात्रा में मक्का का उत्पादन किया जाता है। गुजरात के करीब 4.23 लाख हेक्टेयर में मक्का का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश का प्रतिवर्ष उत्पादन करीब 6 लाख टन है।

सब्जी व फलों की खेती पर मिलेगी सबसिडी

मोगा 7 पंजाब राज्य के बागवानी विभाग द्वारा किसानों का खास खयाल रखा जा रहा है7 राज्य में सब्जियों और फलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को सबसिडी दी जा रही है7 इस स्कीम के तहत बागवानी विभाग मोगा की ओर से जिले में 11 पोली हाउस लगाए गए हैं। सरकार की और से किसानों को 4,67,500 रुपये प्रति पोली हाऊस सबसिडी दी गई है। इसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर अर्श दीप सिंह थिंद ने दी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 3 कोल्ड स्टोरेज बनाए है । जिन पर किसान को 40 प्रतिश्त की वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की ओर से 15 हजार प्रति बक्से के हिसाब से पचास बक्सों पर सबसिडी दी जा रही है7 डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मोगा में सब्जीयों की बढोतरी के लिए जिले में 7,583 हैक्टेयर क्षेत्र सब्जीयों के अधीन लाया गया है। जिसमें आलू ,प्याज, गोभी, टमाटर, बेलोंवाली सब्जीयां, जड़वाली सब्जीया तथा अन्य सब्जीयों की पैदावार होती है। साथ ही 4075 हेक्टेयर क्षेत्र पर तेल निकालने वाली फसल, मसालेदार फसल,व फूलों की पैदावार होती है7 जिससे जिले में बागों का क्षेत्र बढ़ाया है। डीसीश्री थिंद ने बताया कि जिले के गांव बीड़ चड़िक में 75 एकड़ का सरकारी सब्जी बीज फार्म है। जिसमें आलू व अन्य सब्जीयों के प्रमाणित बीज तैयार कर किसानों को बीज पहुंचाए जाते है। किसानों को सरकार की ओर से निर्धारित रेटों पर सब्जीयों के बीज सप्लाई किए जाते है। साथ ही किसानों को सरकार की ओर से दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है।

खरीफ की फसलों का भंडारण

रायपुर। चालू खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़ में अब तक विभिन्न खरीफ फसलों के करीब सात लाख 12 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज का भंडारण किया था। इनमें से छ: लाख 22 हजार क्विंटल से ज्यादा बीज किसानों को वितरित किए गए हैं। कुल भंडारित प्रमाणित बीज का 87 फीसदी किसानों को वितरित किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी कृषि उत्पादन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई खरीफ फसलों की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी। समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रदेश के सभी राजस्व संभागों में किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध हैं। अत: इनके वितरण में आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए किसानों को उनके जरूरत के अनुसार खाद और बीज उपलब्ध कराएं। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 01 जून से अब तक 316 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। मानसून की सक्रियता के चलते यहां बोनी का कार्य जोरों पर है। प्रदेश में अब तक खरीफ फसलों की 41 फीसदी बोनी पूरी हो गई है। बैठक में उन्होंने बताया कि धान की बोनी प्रस्तावित रकबे के 44 प्रतिशत, मक्के की 45 प्रतिशत और सोयाबीन की 77 प्रतिशत क्षेत्र में पूरी हो चुकी है। चालू खरीफ मौसम के दौरान अब तक अनाज फसलों की बुआई 44 प्रतिशत, दलहन की 11 प्रतिशत और तिलहन की 35 प्रतिशत रकबे में हो चुकी है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त को अधिकारियों ने अवगत कराया कि इस साल वनांचलों के वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को भी धान और मक्के के कुल 39 हजार 868 क्विंटल बीज मिनीकिट अब तक बाटे जा चुके हैं। खाद वितरण की जानकारी देते हुए बैठक में मार्कफेड के अधिकारियों ने बताया कि सहकारी समितियों के गोदामों में 08 जुलाई तक पांच लाख 30 हजार मीटरिक टन से अधिक उर्वरक का भंडारण कर इनमें से तीन लाख 57 हजार मीटरिक टन उर्वरक किसानों को वितरित किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन

नई दिल्ली। पिछले 25 सालों से दिल्ली सरकार दिल्ली में 'अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव' का आयोजन कर रही है7 इस महोत्सव की खास बात यह है कि यहाँ पर हर किस्म का आम देखने को मिलाता है7 साथ ही दुनियाभर में आम के प्रति लोगों की चाहत भी समझ आती है। दुनिया भर में आम का जो उत्पादन होता है उसमें 54 प्रतिशत आम की किस्में भारत से जुड़ी होती है7 इतना ही नहीं पूरे विश्व का 46 प्रतिशत आम भारत में पैदा होता है7 भारत में सिर्फ मरूस्थल और समुद्रतल से 1000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़कर पूरे देश में आम की पैदावार होती है7 विश्व में आम की 1365 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती है, जिसमें से लगभग 1000 किस्में भारत में ही पाई जाती है7 भारत में 1.23 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर आम की खेती होती है, जिसमें 11 मिलियन टन की पैदावार होती है। आम महोत्सव में दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग पिछले 25 सालों से आम की पारंपरिक किस्में और विकसित की जा रही किस्मों को पेश करता है7 इस बार 28 से 30 जून तक चले 25 वें आम उत्सव में अंगूर के आकार से लेकर कटहल के आकार तक के आमों को प्रदर्शित किया गया7 इनमें आमों की दुर्लभ किस्में भी मौजूद होती है7 इन दुर्लभ किस्मों में सीकरी, स्वर्ण,जहांगीर, नीलेश्वर, रायलएसपी आदि नाम शामिल है7 इसके अलावा आम की लोकप्रिय किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, सफेदा, केसर, तोतापरी, वनराज जैसे आम भी यहां मौजूद रहते हैं। देखने के आलावा इसके स्वाद का आनंद भी ले सकते है। कई तरह की आम प्रतियोगिता का भी यहाँ आयोजन किया जाता है।

अच्छी नस्ल के पशुओं के संवर्धन के लिए मिलेगा अनुदान

गाजीपुर । पशुपालन में भी अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कामधेनु योजना में कुछ बदलाव किये है7 जिसके चलते सरकार पशुपालक को अच्छी नस्ल के पशुओं को पालने के लिए एक करोड़ बीस लाख रुपये का अनुदान देगी। इस योजना के तहत जिले से एक पशुपालक को चुना जाएगा। उसे 100 जानवर रखने होंगे। इसमें पशुओं की बेहतर प्रजातियां जैसे जर्सी, फ्रिजियन, साहिवाल तथा मुर्रा भैंसे होंगी। उनके बछड़ों को बेहतर प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिले में गाय और भैंसों की कमी नहीं है7 परंतु अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है7 इनका संवर्धन करने के लिए यह योजना बनाई गई है7 इसे चालू करने के लिए 65 जिलों को चुना गया है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। इसके अलावा समिति में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी होंगे। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. एसपी यादव ने कहा कि इस योजना के लिए संपन्न पशुपालक को चुना जाएगा जो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे सके। यह चुनाव पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।